RTI REQUEST DETAILS

Registration No. :	WLIOI/R/2019/80020	**Date of Receipt :**	12/12/2019
Transferred From :	Ministry of Environment, Forest and Climate Change on 12/12/2019 With Reference Number : MOENF/R/2019/00870/2		
Remarks :	**Information sought Autonomous Institute**		
Type of Receipt :	Electronically Transferred from Other Public Authority	**Language of Request :**	English
Name :	Balbeer Singh Chouhan	**Gender :**	Male
Address :	H.No. 1, Lane 1, Mahima Enclave, Kehari Nagar, PO Chandanwadi, Prem Nagar, Dehradun UK, Pin:248007		
State :	Details not provided	**Country :**	Details not provided
Phone No. :	Details not provided	**Mobile No. :**	Details not provided
Email :	Details not provided		
Status(Rural/Urban) :	Details not provided	**Education Status :**	Details not provided
Letter No. :	Details not provided	**Letter Date :**	31/10/2019
Is Requester Below Poverty Line ? :	No	**Citizenship Status**	Indian
Amount Paid :	0 (RTI fee is received by **Ministry of Environment, Forest and Climate Change (original recipient))**	**Mode of Payment**	Details not provided.
Does it concern the life or Liberty of a Person ? :	No(Normal)	**Request Pertains to :**	
Information Sought :	Please find the attached scan file		
Original RTI Text :	Please find the attached scan file		

Print Save Close

IMMEDIATE/RTI MATTER

No. 2/2/2019 – RTIC/04169
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel and Training

North Block, New Delhi-110001
Dated the 31st October, 2019

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Transfer of RTI application under RTI Act, 2005

An RTI application of Shri Balbeer Singh Chouhan, dated 26.10.2019 (reg. No. DOP&T/R/2019/04169), is being transferred under Section 6(3) of the RTI Act 2005, to Department of Expenditure and Ministry of Environment, Forest and Climate Change as the subject matter of information sought pertains to the aforementioned public authority. The RTI Application is also being forwarded to the CPIO concerned of this Department to provide information as available in the records of DOP&T.

2. Application fee of Rs. 10/- has been received in this Department by IPO No. 51F 043743 vide receipt No. 42184 dated 30.10.2019.

Encl.: as above.

(A.K.Singh)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel: 011 2309 4579

To

(1) The CPIO, RTI Cell,
Department of Expenditure,
5th Floor, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi- 110003.

(2) The CPIO, RTI Cell,
Ministry of Environment, Forest and Climate Change,
Indira Paryavaran Bhavan, Prithvi Wing,
6th Floor, Jor Bagh Road, Ali Ganj,
New Delhi- 110003.

RTI Cell
Application/Appeal No. MOEF R/2019/870
App. Dated 31.X Received on 28/11
Fee/Additional fee Received vide I.P.O. No. Transferred from Dopt
Name of CPIO/AA MD Hipal

(3) CPIO & US (Estt.D-II), DOPT

(4) CPIO & US (CS-II.B), DOPT

Copy for information to:-

Shri Balbeer Singh Chouhan, H No. 1, Lane No. 1 Mahima Enclave, Kehari Gaon, PO- Chandanwadi, Prem Nagar, Dehradun, UK- 248007.	यह आपके उपर्युक्त सुचना के आवेदन का जवाब नहीं हे ! आपके सुचना के अधिकार आवेदन को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आर टी आई प्रकोष्ट द्वारा ऐसे केंद्रीय लोक सुचना अधिकारीयों/प्राधिकारियों/मंत्रालयों को हस्तांतरित किया जा रहा हे जो विषय का निपटान कर सकते हे और इसलिए उपर्युक्त केंद्रीय लोक सुचना अधिकारी/प्राधिकारी ही आपके आवेदन का जवाब देंगे ! अतः आपसे अनुरोध किया जाता हे कि आपके द्वारा मांगी गयी सुचना के सन्दर्भ में ऊपर उल्लिखित लोक प्राधिकारी से संपर्क करे ! आपके आवेदन में बिन्दु स.1 और 4 मे मांगी गयी केंद्र सरकार/Autonomous Body के मिनिस्टेरियल / लिपिक वर्ग के एमएसीपी के बाद पदोन्नति/ MACP की सूचना संबन्धित पद के भर्ती नियम मे उपलब्ध होगी जो की सभी मंत्रालयों / Autonomous Body मे उपलब्ध होगी और इस विभाग मे सारे Autonomous Body की सुदचना / RRआरआर संकलित नहीं होती है और सुचना अधिकार अधिनियम के धारा 6 (1) और इस विभाग के OM. स. 10/2/2008-IR dated 12/06/2008 (जिसको CIC ने अपने आदेश स.CIC/OOCMD/A/2016/305357 दिनांक 19.06.2017 द्वारा सही ठहराया है) में दिए गए प्रावधान के अनुसार आप प्रत्येक / संभंधित मंत्रालय / Autonomous Body में अलग अलग आवेदन देकर यह सुचना उपलब्ध कर सकते है! मंत्रालयों / विभागों की सूचि rtionline.gov.in और rti.gov.in पर उपलब्ध है! .इस विभाग द्वारा संचालित केंद्रीय लिपिक सेवाओं की उपलब्ध सुचना यदि हो और MACP पॉलिसी से संभन्धित जो भी सूचना हो आपको उपलब्ध कराने हेतु आपका आवेदन इस पत्र द्वारा ऊपर उल्लेखित सुचना अदिकारियों को भेजा जा रहा है ! धारा ६(३) के तहत स्थानांतरित किया जा रहा है ! पे / पाय कमिशन का विषय व्यय विभाग से है जिसको आपका आवेदन भेजा जा रहा है ! आप से अनुरोध किया जाता हे कि आपके द्वारा मांगी गयी सुचना के सन्दर्भ में ऊपर उल्लिखित लोक प्राधिकारी से संपर्क करे ! उप्रुक्त लोक प्राधिकरण के जवाब से असंतुष्ट होने पर प्रथम अपील आप सीधे उप्रुक्त लोक प्राधिकरण में भेज सकते है ! यदि आप उपर्युक्त आवेदन के स्थानातरण से असंतुष्ट हो तो आप प्रथम अपीलीय अधिकारी, श्री जुगलाल सिंह, उप सचिव (प्रशासन) डी ओ पि टी, नार्थ ब्लाक नई दिल्ली – ११०००१ - दूरभाष - 23092338, के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकते हे..

multiple CPIOs

① US[Estt D-II] ② D/o Expd. ③ M/o Environment & Forest ④ Vasanth V. Babu US(Estt.B) 04168/RTIC/2019 30/10/19

Speed Post

दिनांक: 26/10/2019

04169/RTIC/2019 30/10/19

प्राप्त हुआ RECEIVED IN C.R. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग Deptt. of Personnel & Trg. OCT 2019

सेवामें,

CPIO (RTI Cell)
Under Secretary
Ministry of Personal, Public and Pensions
Department of Personal & Training
North Block, New Delhi- 110001

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत मांगी जाने वाली सूचना के लिए आवेदन पत्र।

1. अनुरोध कर्ता का नाम : श्री बलबीरसिंह चौहान। 04169/1/RTIC/2019 30/10/19

2. पिता का नाम : श्री जयसिंह चौहान।

3. निम्नलिखित सूचना आपके कार्यालय से मांगी जाने का स्पष्ट विवरणः– 4 30/10/19

1. यह है कि भारत सरकार के सभी केंद्रीय व **Autonomus** संस्थानों में, मिनिस्टीरीअल वर्ग के कर्मचारीयों को जैसेकि उच्च श्रेणी लिपिक व अवर श्रेणी लिपिक वर्ग के कर्मचारीयों को भारत सरकार के नियमानुसार कितने–कितने आर्थिक लाभ पत्रांक संख्या DOPT, M.O. No.35034/3/2008-Estt. (D) dated 19/05/2009 के भारत सरकार के आदेशानुसार, MACPS (Modified Assured Career Progression Scheme As per order, three financial upgradations at intervals of 10, 20 and 30 years of continuous regular service is allowed procedure laid down in the said O.M. Copy के अनुसार जिन कर्मचारीयों व अधिकारीयों को कार्यालय द्वारा अगर **3-3 Financial upgradations** आर्थिक लाभ दिये गये हैं उन कर्मचारीयों व अधिकारीयों को आर्थिक लाभ दिये जाने पर भी उसके बाद कितनी–कितनी पदोन्नति दी जा सकी है व पदोन्नति का लाभ और दिया जा सकता है यानी की उनकी पदोन्नति कब–कब होने चाहिए के बारे में स्पष्ट सूचना उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

जबकि **DOPT, M.O. No.35034/3/2008-Estt. (D) dated 19/05/2009** के अनुसार उच्च श्रेणी लिपिक व अवर श्रेणी लिपिक के कर्मचारीयों को इस संलग्न पत्रांक के द्वारा **3-3 financial upgradations benefits** का लाभ प्रथम आर्थिक लाभ दिसम्बर, वर्ष 2009 में, रू0 2400/– ग्रेड पे से रू0 2800/–, ग्रेड पे का दिया गया है।

द्वितीय आर्थिक लाभ मार्च, 2010 में ग्रेड पे रू0 4200/– का दिया गया है और तिसरा आर्थिक लाभ वर्ष अप्रैल, 2017 में ग्रेड पे रू0 4600/– का दिया गया है। जबकि इन कर्मचारीयो की सरकारी सेवाकाल का समय 30 वर्ष से कम का है।

2. यह है कि यह सब आर्थिक लाभ दिये जाने के बाद भी उन सभी कर्मचारीयों को आज की तिथि में 7वें वेतनन आयोगानुसार अक्टूबर, 2019 को सभी कर्मचारीयों को नये सिरे फिर से **MACP** का लाभ दिये जाने के बाद भी तीन–तीन पदोन्नतियां दिये जाने पर और उन कर्मचारीयों को किसी को ग्रेड रू0 6600/– का लाभ, व कुछ कर्मचारीयों को ग्रेड पे रू0 7600/– का लाभ और एक कर्मचारी (अधिकारी) को ग्रेड पे रू0 8700/– (प्रशासनिक अधिकारी को) का दिया जा रहा है के बारे में स्पष्ट सूचना देने की कृपा करें।

(Copy enclosed - Annexure-I).

3. यह है कि पत्रांक संख्या DOPT, M.O. No.35034/3/2008-Estt. (D) dated 19/05/2009 के भारत सरकार के आदेशानुसार, MACPS (Modified Assured Career Progression Scheme **As per order, three financial upgradations benefits** का लाभ देने के पश्चात् भी भारत सरकार के जिस नियमानुसार पदोन्नतियां देने का प्रावधान है की स्पष्ट सूचना देने की कृपा करें।

4. यह है कि पत्रांक संख्या **DOPT, M.O. No.35034/3/2008-Estt. (D) Dated 19/05/2009** के भारत सरकार के नियम के आदेशानुसार, अगर **3-3 Financial upgradations** आर्थिक लाभ मिले व दिये गये हैं तो उन कर्मचारीयों की पदोन्नति जिस उच्च ग्रेड पे तक दी जा सकती व हो सकती है की स्पष्ट सूचना देने की कृपा करें।

5. यह है कि सभी भारत सरकार के संस्थानों में, निजि संस्थानों में, (An Autonomous Institute of Govt. of India) Under the Ministry of Environment & Forests, Climate Change, New Delhi जैसे–ICFRE, Wildlife Institute of India, (Dehradun) ICFRE, etc. प्रशासनिक अधिकारी, वित्त अधिकारी, सेक्सन अधिकारीयों के पदों पर नियुक्त कर्मचारीयों को 7वे वेतन आयोगानुसार वर्तमान में, उनको मिलने वाले जो वेतनमान, पे मैट्रिक्स लेवल व ग्रेड पे भारत सरकार के नियमानुसार जो दिया जा रहा है मिल रहा है उसके बारे में स्पष्ट सूचना उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

6. यह है कि सलग्न वित्त मंत्रालयों के पत्रांक सं0–F.No.39-2/2016-TS.1 (pt) dated 3rd November, 2017, Ministry of Finance Department of Expenditure E III (A) Branch, dated 26th October, 2015 के अनुसार Non-Productivity All Institutes as - ICFRE, Dehradun, and Wildlife Institute of India, Dehradun को वर्ष 2016–17 व वर्ष 2017–2018 व वर्ष 2018–2019 का निम्न वर्ग के कर्मचारीयों को दीपाली में, मिले जाने वाले बोनस का लाभांश दिया जा सकता है के बारे में स्पष्ट सूचना देने की कृपा करें।

(Copy enclosed - Annexure-II to V).

7. यह है कि पर्यावरण एव वन मंत्रालय, स्वायतशासी संस्थान **(Non-Productivity Bonus, Ad-hoc Bonus)** के कर्मचारीयों को दीपावली के त्यौहार का आर्थिक लाभांश मिल सकता है जबकि संलग्न वित्त मंत्रालय के पंत्राक संख्या **No.7/4/2014/E.III (A) dated 19th September, 2017 and F.No.39-2/2016-TS.1 (pt.) Ministry of Human Resource Development** ने भी स्पष्ट किया गया है कि **Grant Non-Productivity Bonus Extension for Autonomus Bodies-reg.** के बारे में स्पष्ट सूचना उपलब्ध करवाने की कृपा करें कि पर्यावरण मंत्रालय, वन और जलवायु परिवर्तन, इंदिरा पर्यावरण भवन के अर्न्तगत जो कार्यालय आते हैं उन्हें इसका लाभ मिल सकता है या नहीं के बारे में स्पष्ट सूचना देने की कृपा करें। कापी उपरोक्त संलग्न है।

8. यह है कि उपरोक्त सभी बिंदुओं पर प्रार्थी को हिन्दी में, समयावधिनुसार सूचना उपलब्ध करवाने, दिये जाने की कृपा करें।

नोटः यदि सूचना आपके कार्यालय से सम्बन्ध नहीं रखती है तो सूचना अधिनियम की धारा 6 (3) के प्रावधानुसार आप इसे सम्बन्धित कार्यालय को फॉरवर्ड कर देवें और उसकी एक प्रति हमें भी भेजने की कृपा करें।

9. आवेदन कर्ता द्वारा जमा शुल्क करने का प्रमाण–पत्र : धनराशि रू010/–का भारतीय पोस्टल आर्डर न0–51F 043743 दिनांक 26/10/2019 को शुल्क के रूप में संलग्न है।

10. आवेदन पत्र जमा करने की तिथि : दिनांक 26–10–2019 को स्पिड पोस्ट से प्रेषित है।

11. आवेदक के हस्ताक्षर : बलबीरसिंह चौहान 26-10-2019

(बलबीरसिंह चौहान)
मकान न0–1, लेन0–1 महिमा एनक्लेव
केहरी गॉव, पो0ऑ0–चंदनवाड़ी,
प्रेमनगर, देहरादून–248007, उत्तराखण्ड

Sh. Hareshkr.
To (RT)

Annexure – I

Annexure – 6.1

IMMEDIATE

No.35034/3/2008-Estt. (D)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
(Department of Personnel and Training)

....

North Block, New Delhi, the 19th May, 2009

OFFICE MEMORANDUM

SUBJECT: - MODIFIED ASSURED CAREER PROGRESSION SCHEME (MACPS) FOR THE CENTRAL GOVERNMENT CIVILIAN EMPLOYEES.

*****

The Sixth Central Pay Commission in Para 6.1.15 of its report, has recommended Modified Assured Career Progression Scheme(MACPS). As per the recommendations, financial upgradation will be available in the next higher grade pay whenever an employee has completed 12 years continuous service in the same grade. However, not more than two financial upgradations shall be given in the entire career, as was provided in the previous Scheme. The Scheme will also be available to all posts belonging to Group "A" whether isolated or not. However, organised Group "A" services will not be covered under the Scheme

2. The Government has considered the recommendations of the Sixth Central Pay Commission for introduction of a MACPS and has accepted the same with further modification to grant three financial upgradations under the MACPS at intervals of 10, 20 and 30 years of continuous regular service .

3. The Scheme would be known as "*MODIFIED ASSURED CAREER PROGRESSION SCHEME (MACPS) FOR THE CENTRAL GOVERNMENT CIVILIAN EMPLOYEES.* This Scheme is in supersession of previous ACP Scheme and clarifications issued there under and shall be applicable to all regularly appointed Group "A", "B", and "C" Central Government Civilian Employees except officers of the Organised Group "A" Service. The status of Group "D" employees would cease on their completion of prescribed training, as recommended by the Sixth Central Pay Commission and would be treated as Group "C" employees. Casual employees, including those granted 'temporary status' and employees appointed in the Government only on adhoc or contract basis shall not qualify for benefits under the aforesaid Scheme. The details of the MACP Scheme and conditions for grant of the financial upgradation under the Scheme are given in Annexure-I.

4. An Screening Committee shall be constituted in each Department to consider the case for grant of financial upgradations under the MACP Scheme. The Screening Committee shall consist of a Chairperson and two members. The members of the Committee shall comprise officers holding posts which are at least one level above the grade in which the MACP is to be considered and not below the rank of Under Secretary equivalent in the Government. The Chairperson should generally be a grade above the members of the Committee.

Illustration-I

The pre-revised hierarchy (in ascending order) in a particular organization was as under:-

Rs. 5000-8000, Rs. 5500-9000 & Rs. 6500-10500.

(a) A Government servant who was recruited in the hierarchy in the pre-revised pay scale Rs. 5000-8000 and who did not get a promotion even after 25 years of service prior to 1.1.2006, in his case as on 1.1.2006 he would have got two financial upgradations under ACP to the next grades in the hierarchy of his organization, i.e., to the pre-revised scales of Rs. 5500-9000 and Rs. 6500-10500.

(b) Another Government servant recruited in the same hierarchy in the pre-revised scale of Rs. 5000-8000 has also completed about 25 years of service, but he got two promotions to the next higher grades of Rs. 5500-9000 & Rs. 6500-10500 during this period.

In the case of both (a) and (b) above, the promotions/financial upgradations granted under ACP to the pre-revised scales of Rs. 5500-9000 and Rs. 6500-10500 prior to 1.1.2006 will be ignored on account of merger of the pre-revised scales of Rs. 5000-8000, Rs. 5500-9000 and Rs. 6500-10500 recommended by the Sixth CPC. As per CCS (RP) Rules, both of them will be granted grade pay of Rs. 4200 in the pay band PB-2. After the implementation of MACPS, two financial upgradations will be granted both in the case of (a) and (b) above to the next higher grade pays of Rs. 4600 and Rs. 4800 in the pay band PB-2.

6. In the case of all the employees granted financial upgradations under ACPS till 01.01.2006, their revised pay will be fixed with reference to the pay scale granted to them under the ACPS.

6.1 In the case of ACP upgradations granted between 01.01.2006 and 31.08.2008, the Government servant has the option under the CCS (RP) Rules, 2008 to have his pay fixed in the revised pay structure either (a) w.e.f. 01.01.2006 with reference to his pre-revised scale as on 01.01.2006; or (b) w.e.f. the date of his financial upgradation under ACP with reference to the pre-revised scale granted under ACP. In case of option (b), he shall be entitled to draw his arrears of pay only from the date of his option i.e. the date of financial upgradation under ACP.

6.2 In cases where financial upgradation had been granted to Government servants in the next higher scale in the hierarchy of their cadre as per the provisions of the ACP Scheme of August, 1999, but whereas as a result of the implementation of Sixth CPC's recommendations, the next higher post in the hierarchy of the cadre has been upgraded by granting a higher grade pay, the pay of such employees in the revised pay structure will be fixed with reference to the higher grade pay granted to the post. To illustrate, in the case of Jr. Engineer in CPWD, who was granted 1st ACP in his hierarchy to the grade of Asstt. Engineer in the pre-revised scale of Rs.6500-10500 corresponding to the revised grade pay of Rs.4200 in the pay band PB-2, he will now be granted grade pay of Rs.4600 in the pay band PB-2 consequent upon upgradation of the post of Asstt. Enggs. in CPWD by granting them the grade pay of Rs.4600 in PB-2 as a result of Sixth CPC's recommendation. However, from the date of implementation of the MACPS, all the financial upgradations under the Scheme should be done strictly in accordance with the hierarchy of grade pays in pay bands as notified vide CCS (Revised Pay) Rules, 2008.

Contd..P-6/-

F.No.39-2/2016-TS.1(pt.)
Government of India
Ministry of Human Resource Development
Department of Higher Education
Technical Section-1
*****

Shastri Bhawan, New Delhi
Dated the 3rd November, 2017

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Grant of Non-Productivity Linked Bonus (Ad-hoc Bonus) to Central Government Employees for the year 2015-16 and 2016-17 – Extension of orders to Autonomous Bodies – reg

The undersigned is directed to say that the orders for payment of Non-Productivity Linked Bonus (ad-hoc bonus) to eligible employees of the Autonomous Bodies have not been issued for 2015-16 and 2016-17. This Ministry has been receiving letters from these institutes as well as representations from employees in this regard.

2. In view of the above, it is requested that the orders for grant of non-productivity linked bonus (ad-hoc bonus) for the year 2015-16 and 2016-17 to the employees of Automous Bodies including IITs may please be issued so that the same could be endorsed to the Institutes.

(Kundan Nath)
Under Secretary to the Government of India
Ph. No. 011- 23381698

Ministry of Finance,
Department of Expenditure,
(Shri Amar Nath Singh, Director, E III-A Branch)
North Block, New Delhi.

Copy for information to Registrars of all IITs.

payable will be (Rs.1200x30/30.4 i.e.Rs.1184.21 (rounded off to Rs.1184/-). In cases where the actual emoluments fall below Rs.1200/- p.m., the amount will be calculated on actual monthly emoluments.

(iv) All payments under these orders will be rounded off to the nearest rupee.

(v) Various points regarding regulation of Ad-hoc / Non- PLB Bonus are given in the Annexure.

3. The expenditure on this account will be debitable to the respective Heads to which the pay and allowances of these employees are debited.

4. The expenditure to be incurred on account of Non-PLB (Ad-hoc Bonus) is to be met from within the sanctioned budget provision of concerned Ministries/Departments for the current year.

5. In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

(Amar Nath Singh)
Director.

To,

All Ministries/Departments of the Government of India as per standard list etc.

Copy (with usual no. of spare copies) forwarded to C&AG, UPSC etc. as per standard list.

Annexure-IV

केंद्रीय विद्यालय संगठन/Kendriya Vidyalaya Sangathan
18, संस्थानिक क्षेत्र/ 18, Institutional Area
शहीद जीत सिंह मार्ग/ Shaheed Jeet Singh Marg
नई दिल्ली–16/ New Delhi - 16
Phone No. 011-26523070

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

F.No.125-8/2003-04/KVS (Budget) **Dated: 07-11-17**

A Copy of letter No.39-2/2016-TS.1 (pt.) dated 3rd November, 2017 of Under Secretary to the Govt. of India, Ministry of HRD, Department of Higher Education, Technical Section-1 addressed to the Ministry of Finance, Dept. Of expenditure regarding Grant of Non-Productivity Linked Bonus (ad-hoc bonus) to Central Government Employees for the year 2015-16 and 2016-17 – Extension of orders to Autonomous Bodies, is forwarded herewith for information. Bonus for the year 2015-16 and 2016-17 may not be paid to the employees till the orders are issued by Dept. of Expenditure

एस.मुथुशिवम्
07/11/17
(एस मुथुशिवम)
उपायुक्त (वित्त)
011-26523070

प्रतिलिपि :

1. उपायुक्त, के. वी. एस. , सभी क्षेत्रीय कार्यालय।
2. वित्त अधिकारी , के. वी. एस. , सभी क्षेत्रीय कार्यालय।
3. सभी अधिकारी / अनुभाग , के. वी. एस. (मु.)।
4. प्राचार्य , के. वी. काठमांडू , मास्को एवं तेहरान ।
5. महासचिव , सभी मान्य संघ ।
6. निदेशक , जीट ग्वालियर , मुंबई , मैसूर , चंडीगढ़ एवं भुबनेश्वर।
7. उपायुक्त, ई डी पी , के वी एस (मु .) को इस निवेदन के साथ की पत्र को के वी एस (मु.) की वैबसाइट के शीर्ष "सूचना पट(Announcements) " के अंतर्गत अपलोड करें ।
8. आर टी आई , के वी एस (मु .)।
9. गार्ड फ़ाइल

F.No.39-2/2016-TS.1(pt.)
Government of India
Ministry of Human Resource Development
Department of Higher Education
Technical Section-1
*****

Shastri Bhawan, New Delhi
Dated the 3rd November, 2017

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Grant of Non-Productivity Linked Bonus (Ad-hoc Bonus) to Central Government Employees for the year 2015-16 and 2016-17 – Extension of orders to Autonomous Bodies – reg

The undersigned is directed to say that the orders for payment of Non-Productivity Linked Bonus (ad-hoc bonus) to eligible employees of the Autonomous Bodies have not been issued for 2015-16 and 2016-17. This Ministry has been receiving letters from these institutes as well as representations from employees in this regard.

2. In view of the above, it is requested that the orders for grant of non-productivity linked bonus (ad-hoc bonus) for the year 2015-16 and 2016-17 to the employees of Autonomous Bodies including IITs may please be issued so that the same could be endorsed to the institutes.

(Kundan Nath)
Under Secretary to the Government of India
Ph. No. 011- 23381698

Ministry of Finance,
Department of Expenditure,
(Shri Amar Nath Singh, Director, E III-A Branch)
North Block, New Delhi.

Copy for Information to Registrars of all IITs.

Annexure-V

हिन्दुस्तान, 5 जुलाई 2019 P.-1

तोहफा : न्यूनतम वेतन की गारंटी देगी सरकार

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'वेतन संहिता विधेयक 2019' को बुधवार को मंजूरी दे दी। इस विधेयक के लागू हो जाने के बाद केंद्र सरकार देशभर के कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन तय करेगी, जिससे कम वेतन राज्य सरकारें नहीं दे पाएंगी।

इस बिल के इसी संसद सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि सरकार की योजना पुराने कई श्रम कानूनों को सरल कर उनकी जगह सिर्फ चार कानून बनाने की है जिसमें यह पहला कानून होगा। विधेयक में प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार रेलवे और खनन समेत कुछ क्षेत्रों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करेगी जबकि राज्य अन्य श्रेणी के रोजगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होंगे। न्यूनतम मजदूरी में हर पांच साल में संशोधन होगा।

अहम प्रावधान

- वेतन भुगतान के लिए सेक्टर और वेतन की अधिकतम सीमा की श्रेणी खत्म की गई।
- अब हर सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी, चाहें उनका वेतन कितना ही क्यों न हो, इसके दायरे में आएंगे।
- न्यूनतम वेतन, बोनस, समान वेतन के लिए कर्मियों द्वारा दावा करने की अवधि को बढ़ाकर तीन साल कर दिया गया है।

> धान का एमएसपी बढ़ा पेज 12

G.A.R. 6
[See Rule 22 (1)]

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
MINISTRY OF PERSONNEL, P.G.& PENSIONS
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)
Website : http://persmin.gov.in

रसीद / RECEIPT

सं. No. 42184

दिनांक / Dated 30/10/19

Received from Balbeer Singh Chauhan, [illegible] Mehuwa Enclave
से प्राप्त Premnagar, UK - 248007.

पत्र सं० / संदर्भ संख्या / Letter No. / Reference No. .... दिनांक / Dated .... / 20......

नगद / बैंकर्स चैक / ड्राफ्ट / भा० पो० ऑ० सं०
In Cash / by Cheque / by Bank Draft on Ten only

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के शुल्क हेतु प्राप्त की।
Account of fee under Right to Information Act, 2005

रुपये / Rs. 10/- SIF- 043743

आद्यहस्ताक्षर / Initials

पदनाम Designation..........